



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 493 /2025

- 1 - चंद्रपाल सिन्हा पिता रोहित कुमार सिन्हा ,36 वर्ष, निवासी गाँव-सरकार, निवासी पिता-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग)
- 2 - धनत @धनक सिन्हा पिता रोहित सिन्हा लगभग 33 वर्ष, निवासी गाँव-सरकार, निवासी पिता-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग)
- 3 - विनोद सिन्हा पिता स्वर्गीय परसराम सिन्हा, 50 वर्ष, निवासी गाँव-सरकार, पी एस. -पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग)

---याचिकाकर्तागण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य-एस. एच. ओ., के द्वारा ,पी. एस.-पिथौरा, जिला-महासमुंद (सी. जी.)

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्तागण हेतु :--श्री राजेश कुमार केशरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :-- श्रीमती. सुनीता माणिकपुरी, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

17/04/2025

1. याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस 2023') की धारा 438 के साथ बीएनएसएस, 2023 की धारा 442 के तहत वर्तमान याचिका विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 17/2025 में पारित दिनांक 18.03.2025 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दायर की है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएस 2023") की धारा 3(5) के साथ धारा 109, 296, 115(2), 351(3) के तहत अपराध के लिए आरोप निर्धारित किए गए हैं।



2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, सत्र प्रकरण क्रमांक 17/2025 में अभियुक्त हैं, जो विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, महासमुंद के समक्ष धारा 109, 296, 115(2), 351(3) सहपठित धारा 3(5) बीएनएस, 2023 के तहत अपराध के लिए लंबित है, जो परिवादी दीपक डडसेना द्वारा किया गये परिवाद पर पुलिस थाना पिथौरा, जिला महासमुंद में पंजीकृत अपराध क्रमांक 186/2024 से उत्पन्न हुआ है।

3. वर्तमान याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 09.09.2024 को प्रातः लगभग 10:00-11:00 बजे जब घायल दीपक डडसेना अपनी पत्नी के साथ हनुमान मंदिर के पास बात कर रहा था, उसी समय याचिकाकर्ता वहां आये और घायल दीपक डडसेना पर लोहे की रॉड और डंडा से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर, आंख, छाती और पीठ पर कई चोटें आईं, साथ ही दाहिने 7 वीं और 8 वीं पसलियों में फ्रैक्चर हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और अंततः याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस, 2023 की धारा 296, 115 (2), 351 (2) और 3 (5) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान, घायल की 09-09-2024 को सीएचसी, पिथौरा में डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई, जिन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:---

“-बाईं आंख के आसपास खून बहना।-दाहिनी कोहनी का घर्षण 2 सेमी।

-दाहिनी भुजा का घर्षण (एकाधिक मंद)-दाहिने घुटने का घर्षण 1 x 1 सेमी।

-एल. डब्ल्यू. 4 x 0.5 खोपड़ी के पार्श्विका क्षेत्र का दाहिना भाग।-पीछे की ओर कई घर्षण।

-एकाधिक पैटर्न घर्षण 10 x 03 आकार।

चिकित्सक ने दो पसलियों का फ्रैक्चर पाया है तथा राय दी है कि पसलियों का फ्रैक्चर गंभीर क्षति है।”

घायल को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, महासमुंद के विशेषज्ञ चिकित्सक से चोटों की जांच रिपोर्ट के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों के एक दल द्वारा घायल की चिकित्सकीय जांच की गई और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:---

“-छाती के दाहिने हिस्से में दर्द होना।

-पीठ के निचले हिस्से तथा लेफ्टिनेंट पैर के पीछे के हिस्से में दर्द।-सिर में दर्द होता है।

-बी. आई. एल. कंधे में दर्द।,

-छाती क्षेत्र पर गहरे दबाव के साथ छाती के आर. टी. पक्ष पर पुराने चोट के निशान।

-लेफ्टिनेंट निचले पेट पर संदूषण 15 x 6 सेमी।

-लेफ्टिनेंट थाई के पार्श्व पहलू पर नील।14 x 14 सेमी.

-सिर के दाहिने पार्श्व भाग पर 4 सेमी आकार का घाव ठीक हो गया है।

-लेफ्टिनेंट की छाती के पिछले हिस्से और लेफ्टिनेंट की ऊपरी बांह के पिछले हिस्से पर कई चोटें हैं।”

घायलों के सिर और छाती का सीटी स्कैन करने पर डॉक्टरों को निम्नलिखित चोटें पाई गईं:---

“सीटी-हेड-डब्ल्यू. एन. एल. नॉर्मल।



–सीटी–चेस्ट–एस/ओ–आरटी. तीसरी पसली तथा चौथी पसली तथा 6,7,8 वीं पसली तथा हल्के हेमोथोरैक्स तथा कोई पिता आई. ओ. अनुमान नहीं।– पसलियों के टूटने के कारण छाती के आर. टी. तरफ कोमलता होती है।”

चूंकि मामले को सर्जरी विभाग द्वारा अंततः सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि वर्तमान में कोई सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और अंतिम राय के लिए भेजा गया था और फिर डॉक्टरों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया:— — —

“1. छाती के दाहिने हिस्से में कई पसलियों का फ्रैक्चर, 6, 7, 8 और 3, एस/ओ को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं कि जीवन के लिए खतरा पैदा हो, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण अंग जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति का संकेत नहीं दे रहा है।

2. सिर पर लगी चोट पहले ही ठीक हो चुकी है और कोई भी इंट्राक्रैनील संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हुई है और अब मरीज होश में है, उन्मुख है, इसलिए सिर पर कोई खतरनाक चोट नहीं देखी गई है।

3. पसलियों के फ्रैक्चर के कारण मरीज को छाती के दाहिने हिस्से में दर्द हो रहा है, लेकिन उसे पहले 05 दिनों के लिए भर्ती कराया गया था और वर्तमान में वह चल-फिर सकता है।

4. सर्जरी विभाग द्वारा दी गई अंतिम राय के अनुसार, निर्धारित दवाइयों के सेवन और नियमित जांच के अलावा किसी सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, दाईं 3, 4, 6, 7, 8 वीं पसलियों में दर्द के साथ फ्रैक्चर होना, बेटे के लिए गंभीर चोट है, लेकिन वर्तमान में उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त खतरनाक नहीं है।”

4. दिनांक 11.09.2024 एवं 14.09.2024 को चिकित्सक से भी पूछताछ की गई, जिसमें चिकित्सक द्वारा बताया गया कि घायल के दाहिने 7 वीं एवं 8 वीं पसली में फ्रैक्चर है, जो गंभीर चोट है, यदि घायल का तत्काल उपचार नहीं किया जाता तो उसकी मृत्यु संभव थी, तथा उसकी मृत्यु जप्त रॉड से लगी चोट से भी संभव हो सकती थी। अन्वेषण पश्चात् याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिथौरा, जिला महासमुंद के समक्ष धारा 296, 115(2), 351(3), 109 एवं 3(5) भादवि 2023 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसे विचारण हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को सौंपा गया है।

5. मामले की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं/आरोपियों द्वारा बीएनएसएस 2023 की धारा 250 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत अपराध नहीं बनता है, क्योंकि चोटों को शुरू में गंभीर प्रकृति का नहीं माना गया था और डॉक्टरों की टीम ने राय दी है कि घायलों के शरीर पर मिली चोटें साधारण प्रकृति की हैं, इसलिए बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के आवेदन को विद्वान विचारण



न्यायालय ने दिनांक 18.03.2025 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है, और उनके खिलाफ आरोप निर्धारित किया गया है, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आरोप पत्र के साथ संलग्न सामग्री से, बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत अपराध का कोई तत्व नहीं है। घायलों के शरीर पर पाई गई चोटें गंभीर नहीं हैं तथा डॉक्टरों की टीम ने यह नहीं कहा है कि पसलियों का फ्रैक्चर घायलों के जीवन के लिए घातक होगा। चोटों की गंभीरता के संबंध में किसी रिपोर्ट के अभाव में, बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत आरोप निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि डॉक्टर, जिसने पूछताछ रिपोर्ट दी, वह घायल का रिश्तेदार है, जिसने अपराध को और अधिक गंभीर बनाने के लिए रिपोर्ट दी और इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त को बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत अपराध से उन्मुक्त किया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि घायलों को मिली चोटों की प्रकृति, जो एमएलसी रिपोर्ट के साथ-साथ चिकित्सा उपचार रिपोर्ट और डॉक्टर से प्राप्त पूछताछ रिपोर्ट से परिलक्षित होती है, अभिलेख पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि चोटें गंभीर प्रकृति की हैं। वैसे भी, बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत अपराध के लिए, चोटों की प्रकृति गंभीर होना आवश्यक नहीं है और केवल आशय के साथ कुछ प्रत्यक्ष कार्य ही बीएनएस 2023 की धारा 109 के तहत अपराध के लिए विचारणीय है। इसलिए, आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने और मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका के साथ संलग्न सामग्री का अवलोकन किया है।

9. राज्य बनाम एस. सेल्वी एवं अन्य, 2018 (13) एस.सी.सी. 455 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय दिया है कि किसी मामले में आरोप निर्धारित करते समय, न्यायालय के पास सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों को छांटने और तौलने का अधिकार है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। एस. सेल्वी (सुप्रा) के मामले में, अपने निर्णय के कंडिका 6 और 10 में, इसने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

“6. इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम प्रफुल्ल सामल, (1979) 3 एससीसी 4; दिलावर बाबू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 2 एससीसी 135; सज्जन कुमार बनाम सीबीआई (2010) 9 एससीसी 368; राज्य बनाम ए.अरुण कुमार (2015) 2 एससीसी 417; सोनू गुप्ता बनाम दीपक गुप्ता (2015) 3 एससीसी 424; उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाढ़ी (2003) 2 एससीसी 711; निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी इत्यादि बनाम जितेंद्र भीमराज बिजय्या (1990) 4 एससीसी 76 और अधीक्षक एवं विधिक मामले, पश्चिम बंगाल बनाम अनिल कुमार भुंजा (1979) 4 एससीसी 274 के मामलों सहित निर्णयों की श्रृंखला में यह सुस्थापित किया गया है कि आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायाधीश सत्र मामलों में संहिता



की धारा 227 के अंतर्गत (जो वारंट मामलों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के समान है) अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों की छानबीन करने और उनका मूल्यांकन करने की निस्संदेह शक्ति है; जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां न्यायालय आरोप विरचित करने में पूरी तरह न्यायसंगत होगा; कुल मिलाकर यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश को यह विश्वास हो जाता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह तो उत्पन्न करते हैं, परंतु गंभीर संदेह उत्पन्न नहीं करते, तो अभियुक्त को दोषमुक्त करने का उसका पूरा अधिकार होगा। न्यायाधीश केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयानों और दस्तावेजों के समग्र प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी कमजोरी आदि पर विचार करना होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष में एक व्यापक जांच करनी चाहिए और सामग्री का वजन करना चाहिए जैसे कि वह एक परीक्षण कर रहा हो।

10. यदि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया यह राय बनाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो सकता है, तो वह आरोप तय कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए यह उचित संदेह से परे साबित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। आरोप निर्धारित करते समय, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाए और यह मान ले कि सामग्री के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। न्यायालय को संहिता की धारा 227 या 239 के स्तर पर अभिलेख पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन केवल यह पता लगाने के लिए करना आवश्यक है कि क्या उससे उभरने वाले तथ्य, यदि अंकित मूल्य पर लिए जाएं, तो कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। यह सामान्य बात है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और ऐसी सामग्री का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करना होता है कि क्या उससे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, अपराध के अवयवों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।"

10. आरोप विरचित करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने और लघु विचारण करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय केवल इस बात पर विचार करेगा कि विचारण को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक, 2019 (13) एससीसी 62 के मामले में सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप निर्धारित करने के चरण में, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि उनसे उभरने वाले तथ्यों को उनके



अंकित मूल्य पर लिया जाए तो कथित अपराध के सभी तत्वों का अस्तित्व प्रकट होता है और आरोप निर्धारित करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की सराहना करने और आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। दीपक (सुप्रा) के मामले में, अपने फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:---

"16. यह भी नोट किया गया कि आरोप विरचित करने के चरण में, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होगा कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है : (चित्रेश कुमार चोपड़ा मामला [चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) , (2009) 16 एससीसी 605 : (2010) 3 एससीसी (क्रि) 367] , एससीसी पी 613, कंडिका 25)

"25. यह सामान्य बात है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे प्राप्त तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध या अपराधों को बनाने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, न्यायालय साक्ष्यों की छानबीन कर सकता है, क्योंकि प्रारंभिक चरण में भी अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सत्य मानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस चरण में, न्यायालय को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होता है कि क्या यह "अनुमान लगाने" का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, न कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है।"

11. मनजीत सिंह विरदी बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ, 2023 (7) एससीसी 633 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 12 में अभिनिर्धारित किया है कि:---

"12. इस विवादक पर विधि को राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप [राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप, (2021) 11 एससीसी 191 : (2022) 1 एससीसी (क्रि) 286] में इस न्यायालय के हालिया फैसले में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किए गए हैं: (एससीसी पृष्ठ 197-98, कंडिका 11)

"11. ... 11.1.पी. विजयन बनाम केरल राज्य [पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398 : (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1488] में, इस न्यायालय के पास धारा 227 सीआरपीसी पर विचार करने का अवसर था। आरोप तय करने और/या डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय क्या विचार किया जाना आवश्यक है, इस पर उक्त निर्णय में विस्तार से विचार किया गया है। यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन करनी है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह देखा गया है कि दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सबूतों या अदालत



के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति शामिल होगी जो स्पष्ट रूप से खुलासा करते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियां हैं। यह भी कहा गया है कि यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह धारा 228 सीआरपीसी के तहत आरोप निर्धारित करेगा, यदि नहीं, तो वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक चित्त का प्रयोग करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या सबूतों और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में न्यायालय का कार्य है, वाद शुरू होने के बाद।

11.2. कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमथ [कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमथ, (2019) 7 एससीसी 515:(2019) 3 एससीसी (क्रि) 109:(2019) 2 एससीसी (एलएंडएस) 380] में इस न्यायालय के हालिया निर्णय में, पीठ की ओर से बोलते हुए हममें से एक (डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने कंडिका 25 में निम्नानुसार अवलोकन और निर्णय दिया है: (एससीसी पृष्ठ 526)

“25. उच्च न्यायालय [हिरेमथ बनाम कर्नाटक राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन कर 4970] को इस तथ्य का संज्ञान होना चाहिए था कि विचारण न्यायालय धारा 239 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत डिस्चार्ज के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहा था। इस क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों को इस न्यायालय के कई फैसलों में अभिव्यक्ति मिली है। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्त के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य, उसके अंकित मूल्य पर, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। राज्य टी.एन. बनाम एन. सुरेश राजन [राज्य टी.एन. बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एससीसी 709 : (2014) 3 एससीसी (क्रि) 529 : (2014) 2 एससीसी (एल एंड एस) 721] में, इस विषय पर पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने : (एन. सुरेश राजन मामला [राज्य टी.एन. बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एससीसी 709 : (2014) 3 एससीसी (क्रि) 529 : (2014) 2 एससीसी (एल एंड एस) 721], एससीसी पृ. 721-22, कंडिका 29)

“29. ... इस स्तर पर, सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाए और यह मान ले कि सामग्री के आधार पर दोषसिद्धि की गारंटी नहीं दी जा सकती। हमारे विचार में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के सत्यापन मूल्य के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए



न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। विधि इस स्तर पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देता है।"

12. इसके अलावा, एसपीई के माध्यम से एसपी द्वारा राज्य के मामले में, सीबीआई बनाम उत्तमचंद बोहरा, 2022 (16) एससीसी 663, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 21 में अभिनिर्धारित किया है :---

"21. सीबीआई बनाम के. नारायण राव [सीबीआई बनाम के. नारायण राव, (2012) 9 एससीसी 512 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 737 : (2012) 3 एससीसी (क्रि) 1183] में, इस न्यायालय ने आपराधिक मामले में अभियुक्तों को मुक्त करने से संबंधित लागू मानक के प्रश्न से निपटने वाले पिछले निर्णयों की समीक्षा करने के बाद, सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया : (एससीसी पृष्ठ 520-23, कंडिका 12-14)

"12. रमेश सिंह [बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, (1977) 4 एससीसी 39 : 1977 एससीसी (क्रि) 533] में पहला निर्णय अभियुक्तों को मुक्त करने या विचारण को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करने के लिए संहिता की धाराओं 227 और 228 की व्याख्या से संबंधित है। उक्त निर्णय के कंडिका 4 को सेवा में लगाया गया है जो निम्नानुसार है: (एस. सी. पी. 41-42)

'4. संहिता की धारा 226 के तहत अभियोजन पक्ष के लिए मामला शुरू करते समय अभियोजक को अभियुक्त के खिलाफ आरोप का वर्णन करना होता है और यह बताना होता है कि वह किस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के अपराध को साबित करना चाहता है। इसके बाद प्रारंभिक चरण में न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वह मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करे और उस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की तर्क सुने। इसके बाद न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश पारित करना होता है। यदि "न्यायाधीश का विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मुक्त कर देगा और ऐसा करने के उसके कारणों को दर्ज करेगा", जैसा कि धारा 227 में आदेश दिया गया है। दूसरी ओर, यदि "न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो -

..... (ख) विशेष रूप से न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप तैयार करेगा", जैसा कि धारा 228 में प्रावधान किया गया है। दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, जैसा कि उन्हें होना चाहिए, यह स्पष्ट होगा कि परीक्षण की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजक द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक न्याय नहीं किया जाना है। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव को कोई महत्व दिया जाना है। विचारण के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह इस बात पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील तराजू पर तौले कि यदि तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो क्या वे अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। अभियुक्त के दोषी होने या न होने के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अंतिम रूप से लागू किए जाने वाले परीक्षण और निर्णय के मानक को



संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले का फैसला करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस चरण में न्यायालय को यह नहीं देखना है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं या क्या मुकदमे का अंत निश्चित रूप से उसके दोषी ठहराए जाने के साथ होगा। यदि मामला संदेह के दायरे में ही रहता है तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रबल संदेह, मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन आरंभिक चरण में यदि प्रबल संदेह है जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की धारणा के लिए आधार है तो न्यायालय के लिए यह कहना उचित नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आरंभिक चरण में अभियुक्त के अपराध की धारणा फ्रांस में आपराधिक मामलों की सुनवाई को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है, जहां अभियुक्त को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को विचारण को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। यदि अभियोक्ता द्वारा अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य, भले ही उसे प्रतिपरीक्षा में चुनौती दिए जाने या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किए जाने से पहले पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया हो, यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो विचारण को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा। परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची जो यह इंगित करती है कि किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, न तो संभव है और न ही उचित है। हम विधि के अंतर को एक और उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं।

यदि विचारण के समापन पर अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में तराजू के पलड़े कुछ हद तक बराबर हों, तो संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामले का अंत उसके दोषमुक्त होने से होगा। लेकिन दूसरी ओर, यदि धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में ऐसा हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो आदेश देना होगा वह धारा 228 के तहत होगा न कि धारा 227 के तहत।'

13. संहिता की धारा 227 के तहत अभियुक्तों को उन्मुक्त करने पर इस न्यायालय द्वारा पी. विजयन [पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398 : (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1488] में व्यापक रूप से विचार किया गया था, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था : (एससीसी पृष्ठ 401-402, कंडिका 10-11)

'10.. यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो ट्रायल जज को अभियुक्त को उन्मुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर उसे यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होने के साथ समाप्त होगा। इसके अलावा,

"अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के आदेश पर आरोप तय करने के लिए मात्र डाकघर नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा



विचारण चलाने के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उसे मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इस तथ्य का आकलन करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में अदालत का कार्य है, विचारण शुरू होने के बाद।

11. धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए सबूतों को छांटना है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में लेगी जो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ संदेहास्पद परिस्थितियाँ हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके।'

14. सज्जन कुमार [सज्जन कुमार बनाम सीबीआई, (2010) 9 एससीसी 368 : (2010) 3 एससीसी (क्रि) 1371] में पुनः उन्हीं प्रावधानों अर्थात् आरोप तय करने और अभियुक्तों को दोषमुक्त करने पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया: (एससीसी पृ. 375-77, कंडिका 19-21)

'19. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक चरण में, यदि कोई प्रबल संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय के लिए यह कहना उचित नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्रारंभिक चरण में अभियुक्त के दोष की जो धारणा बनाई जाती है, उसका उद्देश्य केवल प्रथम दृष्टया यह तय करना है कि न्यायालय को मुकदमा चलाना चाहिए या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करता है, भले ही उसे जिरह में चुनौती दिए जाने या बचाव पक्ष के साक्ष्य, यदि कोई हो, द्वारा खंडन किए जाने से पहले पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो विचारण चलाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा।

20. धारा 209 सीआरपीसी के तहत किसी मामले की जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है और उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि उसके समक्ष मामला अभियुक्त को सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए उपयुक्त है या नहीं। वह अभिलेख पर सामग्री को छानने और तौलने का हकदार है, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि क्या प्रतिबद्धता के लिए पर्याप्त सबूत हैं, न कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यदि प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त कर दे, दूसरी ओर, यदि कोई ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर दोषसिद्धि उचित रूप से आधारित हो सकती है, तो उसे मामले को कमिट करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि धारा 227 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, मजिस्ट्रेट को मामले के पक्ष और विपक्ष में भटकावपूर्ण जांच नहीं करनी चाहिए और साक्ष्य का मूल्यांकन इस तरह नहीं



करना चाहिए जैसे कि वह कोई विचारण चला रहा हो। सीआरपीसी की धारा 227 और 228 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग।

21. संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों द्वारा विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) धारा 227 सीआरपीसी के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास सबूतों को छांटने और तौलने का निस्संदेह अधिकार है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने का परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट होता है, जिसे उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां न्यायालय द्वारा आरोप तय करना तथा मुकदमा चलाना पूरी तरह से न्यायसंगत होगा।

(iii) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों के समग्र प्रभाव तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, किसी भी बुनियादी कमियों आदि पर विचार करना होगा। हालांकि, इस स्तर पर मामले के पक्ष-विपक्ष में कोई जांच नहीं की जा सकती तथा साक्ष्यों का मूल्यांकन इस प्रकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि वह मुकदमा चला रहा हो।

(iv) यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है, यद्यपि दोषसिद्धि के लिए यह निष्कर्ष उचित संदेह से परे साबित होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(v) आरोप विरचित करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन आरोप तय करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर अपना न्यायिक विचार करना चाहिए और इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के चरण में, न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध के सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्यों की छानबीन करें, क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सभी बातों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।



(vii) यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को दोषमुक्त करने का अधिकार होगा और इस चरण में, उसे यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होने के साथ समाप्त होगा।'

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम दिलीपसिंह किशोरसिंह राव, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1294 के मामले में अपने फैसले में आगे कहा है कि:---

"10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य, कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।

11. इस न्यायालय ने टी.एन. राज्य बनाम एन. सुरेश राजन [टी.एन. राज्य बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एससीसी 709 : (2014) 3 एससीसी (क्रि) 529 : (2014) 2 एससीसी (एल एंड एस) 721] में इस विषय पर पहले से निर्धारित कानून के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित किया है: (एस. सी. सी. पीपी. 721-22, कंडिका 29)

29. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ हमारी प्रशंसा करती हैं। यह सत्य है कि आरोपमुक्त के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुख्यपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह पता लगाने के लिए सबूतों की छानबीन कर सकता है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि डिस्चार्ज का आदेश पारित किया जा सके। यह सामान्य बात है कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना पड़ता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन यह पता लगाने के उद्देश्य से करना पड़ता है कि क्या उनके सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस स्तर पर, सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाए और यह मान ले कि सामग्री के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। हमारे विचार में, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया है, न कि यह कि अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है या नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के सत्यापन मूल्य के आधार पर अपराध किया है, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। विधि इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।"



12. अभियुक्त के बचाव पर उस समय विचार नहीं किया जाना चाहिए जब अभियुक्त आरोपमुक्त होना चाहता है। धारा 227 सीआरपीसी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मामले का अभिलेख" को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और लेखों, यदि कोई हो, के रूप में समझा जाना चाहिए। संहिता अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देती है। अभियुक्त का प्रस्तुतीकरण अन्वेषण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए।

13. आरोप विरचित करने के चरण में प्राथमिक विचार एक प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण है, तथा इस स्तर पर, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा [महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, (1996) 4 एससीसी 659:1996 एससीसी (क्रि) 820] और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी [मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी, (2000) 6 एससीसी 338:2000 एससीसी (क्रि) 1110] में अपने पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित करने के चरण में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण करना है। यह आरोप विरचित करने के चरण में भी आयोजित किया जाता है, न्यायालय को अभिकथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के लिए एक अनुमानित राय बनानी होती है तथा यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाए तथा यह जांच करे कि क्या अभिलेख पर सामग्री निश्चित रूप से विचारण के समापन पर दोषसिद्धि का कारण बनेगी।"

14. इसके अलावा राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम शिव चरण बंसल एवं अन्य, 2020 (2) एससीसी 290 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित करने के चरण में विचारण न्यायालय को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच या उसमें व्यापक जांच करने की आवश्यकता नहीं है और उसके पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य को छानने और तौलने का अधिकार है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। आरोप निर्धारित करने के चरण में साक्ष्य के सत्यापन योग्य मूल्य पर गौर नहीं किया जा सकता है।

15. एफआईआर और एमएलसी रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि घायल के शरीर पर कई चोटें पाई गई हैं, जिनमें दाहिनी पसलियों का फ्रैक्चर भी शामिल है, जो गंभीर प्रकृति की हैं, जैसा कि 09.09.2024 को घायल की एमएलसी के समय डॉक्टर ने बताया था। हालांकि, एक राय यह है कि चोट इतनी खतरनाक नहीं थी कि वर्तमान में उसका जीवन खतरे में पड़ जाए, लेकिन चोट को देखते हुए, यानी छाती के दाहिने हिस्से की 03 पसलियों का फ्रैक्चर, यह निश्चित रूप से बीएनएस, 2023 की धारा 116 (आईपीसी की धारा 320) के तहत परिभाषित गंभीर चोटों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, याचिका के साथ पृष्ठ संख्या 51 और 52 पर संलग्न जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर की चोटें गंभीर प्रकृति की हैं और यदि समय रहते उनका उपचार नहीं किया जाता तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी।



16. बीएनएस, 2023 की धारा 109 हत्या के प्रयास को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:---

हत्या का प्रयत्न :

109. (1) जो कोई कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उसने उस कार्य से किसी की मृत्यु कर दी होती तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो अपराधी या तो आजीवन कारावास से या इसमें पूर्व वर्णित दंड से दण्डनीय होगा

(2) जब उपधारा (1) के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दण्डित है, तब यदि चोट पहुंचती है तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जा सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल होगा।"

17. बीएनएस, 2023 की धारा 109 की परिभाषा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य से "चोट" पहुंचती है, तो अपराधी दण्डित होने का अधिकारी होगा। परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "चोट" है न कि "गंभीर चोट"। वर्तमान मामले में, दिनांक 09.09.2024 को उसकी मेडिकल जांच के समय घायल के शरीर पर चोटें पाई गई हैं, जिसमें पसलियों का फ्रैक्चर भी शामिल है। पसलियों के फ्रैक्चर के बारे में डॉक्टर ने राय दी थी कि पसलियों के फ्रैक्चर की चोट की प्रकृति गंभीर चोट है।

18. "हरि मोहन मंडल बनाम झारखंड राज्य" 2004(12) एससीसी 220 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 10 से 14 में अभिनिर्धारित किया है कि:---

"10. ऊपर उल्लेखित तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या धारा 307 आईपीसी लागू होती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"307. जो कोई कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो अपराधी या तो आजीवन कारावास से या इसमें पूर्व वर्णित दण्ड से दण्डनीय होगा।" इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। यद्यपि वास्तव में कारित चोट की प्रकृति अक्सर अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफी सहायता कर सकती है, लेकिन ऐसे आशय को अन्य परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है, और कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के संदर्भ के बिना भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। जहाँ तक हमला किए गए व्यक्ति का संबंध है, ऐसे कार्य से कोई परिणाम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी



ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में पहुंचाई गई चोट सामान्य परिस्थितियों में भी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, धारा में वर्णित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों के तहत किया गया था। आपराधिक होने के लिए प्रयास का अंतिम से पहले का कार्य होना आवश्यक नहीं है। यह विधि में यह पर्याप्त है, यदि इसके निष्पादन में कोई स्पष्ट कार्य के साथ-साथ आशय भी मौजूद हो।

11. धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है कि इसके निष्पादन में कोई प्रत्यक्ष कार्य के साथ-साथ कोई आशय भी मौजूद हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। यदि चोट पहुंचाने का उद्देश्य या इरादा मृत्यु कारित करना है, तो चोट की अनुष्ठानिक प्रकृति, सीमा या चरित्र या क्या ऐसी चोट वास्तव में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, ये सभी ऐसे कारक हैं जो धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय करने के लिए पूरी तरह असंगत हैं। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम के बावजूद, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान और परिस्थितियों के तहत किया गया था। इसलिए, धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करना सही नहीं है क्योंकि पीड़ित को पहुंचाई गई चोटें एक साधारण चोट की प्रकृति की थीं।

12. यह स्थिति महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल, (1983) 2 एससीसी 28 और आर. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य (2004) 9 एससीसी 27 में उजागर हुई थी।

13. सरजू प्रसाद बिहार राज्य, एआईआर 1965 एससी 843, (1965) 1 क्रि एलजे 766 में कंडिका 6 में यह देखा गया था कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा वास्तव में पहुंचाई गई चोट ने पीड़ित के किसी महत्वपूर्ण अंग को नहीं काटा, अपने आप में उस कृत्य को धारा 307 के दायरे से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. क्या हत्या करने का आशय था या यह ज्ञान था कि मृत्यु होगी, यह तथ्य का प्रश्न है और किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह परिस्थिति कि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोट साधारण या मामूली थी, अपने आप में धारा 307 आईपीसी के आवेदन को खारिज नहीं करेगी। निर्णायक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति।"

19. इस वर्तमान प्रकरण में भी आरोप है कि याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तगण ने घायल पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला किया, जिससे उसे पसलियों के टूटने सहित कई चोटें आईं और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार पसलियों का टूटना गंभीर चोट है। घायलों और साक्षियों के बयान और आरोप पत्र में उपलब्ध पूरी सामग्री के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अपराधों के साथ-साथ बीएनएस, 2023 की धारा 109 के तहत आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है। इस स्तर



पर याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरोप निर्धारित करने के चरण में मामले का कोई सूक्ष्म विचारण स्वीकार्य नहीं है।

20. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आधार पर, मुझे उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है तदनुसार इस याचिका को खारिज किया जाता है।

सही/-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

